(ग) उक्त परियोजना को आरंभ करने के लिए क्या मानदण्ड है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी हां । वर्ष 1991–92 के दौरान देश के 100 समुदाय विकास ब्लाकों में नई आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं स्वीकृति की गई हैं । राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या
1. असम	2
2. बिहार	17
3. गुजरात	4
4. हरियाणा	1
5. हिमाचल प्रदेश	1
6. जम्मू व कश्मीर	1
7. कर्नाटक	6
8. केरल	3
9. मध्य प्रदेश	11
10. महाराष्ट्र	10
11. मणिपुर	1
12. मेघालय	1
13. पंजाब	1
14. राजस्थान	5
15. उत्तर प्रदेश	24
16. पश्चिम बंगाल	10
17. अरुणाचल प्रदेश	1
18. दिल्ली	1

(ग) आई०सी० डी० एस० परियोजनाओं के लिए स्थान निर्धारण का निर्णय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों का बाहुल्य तथा शिशु जन्म-दर आदि जैसी बातों पर आधारित कुछ निश्चित मानदण्ड को ध्यान में रख कर ही लिया जाता है ।

पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कार्य

1709. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 1989–90 से 1991–92 के दौरान पुरातत्व विभाग ने खुदाई का कार्य अपने हाथ में लिया था और इन पर स्थलवार कितना खर्च हुआ था ; और

(ख) पुरातत्व विभाग के अधीन कितने स्थलों पर खुदाई का कार्य चल रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) 1989–90 से 1991–92 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संलग्न विवरण (नीचे देखिए) के अनुसार कुछ स्थानों पर उत्खनन-कार्य किये हैं ।

संदर्भाधीन उत्खनन-कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय का स्पष्ट विवरण देना संभव नहीं है, चूंकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, जबकि कुछ मामलों में उत्खनन कार्य इस तिथि से आगे अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ जाता है । उत्खनन-कार्य के अलावा निर्धारित धन राशि का उपयोग तत्सम्बन्धित कार्यों अर्थात् प्रशिक्षण, मानचित्र बनाने, प्रलेखीकरण और निकाली गई संरचनाओं, मिट्टी के बर्तनों, पुरा-वस्तुओं आदि के रखरखाव पर भी किया जाता है ।

विवरण]

1989–90 से 1991–92 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिन स्थानों पर उत्खनन-कार्य किए गए हैं, उनके नामों का विवरण ।

1. आदम, जिला नागपुर, महाराष्ट्र
2. बाराबती किला, जिला कटक, उड़ीसा
3. बानारसिहानकलां, जिला महाराजगंज उ०प्र०
4. बैतबारी जिला पश्चिम गारो हिल्स मेघालय
5. चेरमंगडु जिला त्रिचूर, केरल
6. दाहपार्वतिया, गोलपाड़ा, असम
7. धोलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात
8. दुल्मी, जिला सिंहभूम, बिहार
9. गोलबाई सासन, जिला पुरी- उड़ीसा
10. गुदनापुर, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक
11. हम्पी, जिला बेल्लारि, कर्नाटक
12. कोल्हुआ, वैशाली, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार
13. कर्काभाट, जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश
14. ललितगिरि, जिला कटक, उड़ीसा
15. लालकोट, दक्षिण दिल्ली
16. लाड्यूरा, जिला अल्मोड़ा, उ०प्र०
17. मामल्लपुरम, जिला एम०जी०आर० तमिलनाडु
18. अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
19. सारहा वाराहा, जिला आगरा, उ०प्र०
20. संघोल, जिला लुधियाना, पंजाब
21. सेकता, मणिपुर
22. श्रावस्ती, जिला बहराइच, उ०प्र०
23. सेंट अगस्टाइन चर्च, गोवा
24. उदयागिरि, जिला कटक, उड़ीसा
25. थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा

Indian Institute of Advanced Studies, Shimla

1710. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR;
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT' be pleased to state:

(a) the number of scholars who have been benefited by the scheme of the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, during the last three years;

(b) whether the studies completed by these scholars would be made available in the library of the Parliament; and

(c) what is the annual expenditure of this Institute for the last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) The Indian Institute of Advanced Study, Shimla has awarded fellowship to 138 scholars during the last three calender years. These include Fellows. Associates and Visiting Scholars.

(b) The Annual Report of the Institute is laid before the Parliament every year. Besides, its publications are sent to the Library of Parliament. Government would have no objection to reports of scholars being made available to the Parliament Library on demand.

(c) Government has during the last 3 years provided financial assistance to the Institute as below:

	Rs,
1989-90	103,61,000
1990-91	120,70,000
1991-92	144,00,000